UN, and not outside the purview of the UN. Secondly, it is for each country to decide in which area they will participate and in which area they will not participate. So far as the improvement of defence relations with the USA is concerned, there is no doubt that the direction is to improve the reations--we want to extend our defence cooperation--not only with the USA but with host of other countries all over the world including China, Russia, France, the UK and the USA.

"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के तहत जैव-डीजल का उत्पादन

†*203. श्री रविशंकर प्रसाद:#
श्री राम जेठमलानी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से जैव-डीजल के उत्पादन को "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के अधीन लाने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त मामले पर विचार करके जैव-डीजल के उत्पादन को "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के अधीन शामिल करने का निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सभा में 7.12.2005 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या

(क) से (घ) भारत सरकार ने 7.9.2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जानी है। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करने के अनुदेश दिए गए हैं।

†Original notice of the question was received in Hindi.
#सभा में यह प्रश्न श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा पूछा गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को बायो-डीजल के उत्पादन को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन लाने का अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, जैव-डीजल की उत्पादन प्रक्रिया में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा तिलहन लगाने और इसके उत्पादन को बढ़ाने का प्रथम चरण शुरू किया जा सकता है क्योंकि यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित कार्यों के दायरे में आता है। जैव-उत्पाद को जैव ईंधन में परिवर्तित करने का दूसरा चरण तेल कम्पनियों की मदद से निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।

Production of bio-diesel under National Rural Employment Guarantee Scheme

†*203. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to bring production of bio-diesel under National Rural Employment Guarantee Scheme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have decided to include the production of bio-diesel under NREGS after considering the above matter; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Government of India has notified the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 on 7.9.2005. Under the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), Rural Employment Guarantee Schemes are to be formulated by the State Governments. State Governments have been instructed to formulate Rural Employment Guarantee Schemes under the NREGA. No request to bring production of bio-diesel under NREGA has been received in the Ministry of Rural Development uptill now. However, in the production process of bio-diesel, the first step comprising plantation and raising of oil seeds may be taken up by the State Governments under the National Rural Employment Guarantee Act as this is within the scope of works mentioned in Scheduled-I

†Original notice of the question was received in Hindi.

of the National Rural Employment Guarantee Act. The second step of converting the bio-produce into bio-fuel would have to be taken up in the private/public sector with the help of oil companies.

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सभापति जी, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या बॉयो-डीज़ल के उत्पादन के बारे में सरकार विचार करती है? सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि इन सारे कार्यक्रमों पर निर्णय करने का अधिकार प्रदेश सरकारों को है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राज्य सरकारों को सलाह देती है कि नये-नये कार्यक्रमों के बारें में भी विचार किया जाये, विशेषकर जब देश में ईंधन की कमी है और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अत: जो जटरोफा बीज होते हैं, जिनसे बॉयो-डीज़ल काफ़ी निकलता है, इसको भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उगाया जाये, क्या इसके बारे में आपने प्रदेश सरकारों को कोई सलाह दी है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सवाल है कि नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम का जो कानून बना है उसके अधीन कोई राज्य सरकार से प्रस्ताव आया है कि बॉयो-डीज़ल का उत्पादन हो। महोदय, उसके बारे में हमने कहा है कि बॉयो-डीज़ल के लिए जो जटरोफा ऑयल सीड्स अथवा नन-ऐडीबल ऑयल का जो ऑयल सीड्स है, उसके उत्पादन में कोई हर्ज नहीं है, आलरेडी उसमें प्रावधान है, वैस्ट लैंड डेवलेपमेंट करने का, प्लांटेशन करने का। यदि कोई राज्य सरकार नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम के कानून के अधीन ऑयल सीड्स जटरोफा आदि उत्पादन करने का प्रावधान करे, प्रयत्न करे, तो इसकी पूरी इजाजत है, वह उसका इस्तेमाल कर सकती है।

महोदय, अब सवाल बॉयो-डीज़ल का रहा, जो ऑयल सीड्स से बॉयो-डीज़ल बनेगा, तो उसके लिए मशीन की और प्रशिक्षित मजदूर की जरूरत होगी, तो वह अलग से होगा। वैसे माननीय सदस्य यदि बॉयो-डीज़ल में इंटरेस्टिड हैं, तो आलरेडी नेशनल बॉयो-डीज़ल मिशन प्रोग्राम प्लानिंग कमीशन के द्वारा रिपोर्ट आई, उस पर सरकार ने पूरी तरह से विचार किया है, उसकी डीपीआर बन गई है, हमने प्लानिंग कमीशन में उसको सबमिट कर दिया है, जो TERI के द्वारा डीपीआर बना, वैसे आठ राज्य सरकारों ने अपने आप बॉयो-डीज़ल का उत्पादन करने की शुरुआत कर दी है। उसके साथ ही नॉबार्ड जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अधीन आता है, उन्होंने भी शुरू किया है, रेलवे बोर्ड ने भी शुरू किया है और कई रिसर्च इन्स्टीयूट्स ने भी बॉयो-डीज़ल के उत्पादन के लिए प्रयत्न शुरू किये हैं, इसलिए सरकार बॉयो-डीज़ल के उत्पादन के लिए तत्पर है। जो नेशनल बॉयो-डीज़ल मिशन अंतिम प्रक्रिया में है, डीपीआर सबमिशन के बाद, जैसे ही प्लानिंग कमीशन उसको स्वीकृति दे देगा, उसका विस्तार रूप में कार्यान्वयन शुरू हो जायेगा। देश भर में कम से कम

साढ़े आठ लाख हैक्टेयर ज़मीन जो जंगल की है और जो साढ़े आठ लाख हैक्टेयर ज़मीन, ऐसी ज़मीन है, करीब 17 लाख हैक्टेयर ज़मीन में जटरोफा का उत्पादन किया जा सकता है और इसका प्रबंध हम कर रहे हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी बॉयो-डीज़ल के संबंध में, संबंधित विभाग क्या कार्यवाही कर रहे हैं, इसका ज्ञान मुझे है। मैंने प्रश्न एक विशेष उद्देश्य के लिए पूछा था कि ग्रामीण विकास और नियोजन के बढ़ावे में जटरोफा के उत्पादन में आपकी सरकार की भूमिका क्या है? आपने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि इसकी संभावना है। मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में इसका काफी उत्पादन हो रहा है और वहां के मुख्य मंत्री की गाड़ी जटरोफा के डीज़ल से चल रही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपका विभाग प्रदेश की सरकारों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके उत्पादन से प्रति वर्ष पांच लाख ग्रामीण बेरोज़गारों को काम मिलेगा। तो क्या आपका विभाग इस दिशा में काई सुनियोजित एवं समयबद्ध कार्यक्रम चलाने की इच्छा रखता है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: कोई हर्ज़ नहीं है। राज्य सरकारों को...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, यह क्या उत्तर है? कोई हर्ज नहीं है, बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: बायो डीज़ल का उत्पादन कराने में कोई हर्ज नहीं है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को केवल सुझाव ही नहीं देगी, सहायता भी देगी और प्रयत्न करेगी कि ज्यादा से ज्यादा बायो डीज़ल का उत्पादन हो सके।

डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा: कितनी सहायता देंगे आप? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, the reply tabled by the hon. Minister contains a very curious confession. It says. "No request to bring production of bio-diesel under the NRGA has been received in the Ministry of Rural Development uptill now." Does it mean that your Ministry does not consider anything sensible on its own unless somebody brings it to your brain? And, secondly, are you prepared to assure the House that after this question was actually put to you, your Ministry will consider the enormous potential that this proposal has for decreasing rural unemployment, and that you will not only consider that, that you will not only give help to the State Governments, but you will also activate them and force them to adopt it?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, ऑयल सीड उत्पादन का तो गारंटी कानून में ऑलरेडी प्रावधान है, उसे राज्य सरकार करे। हम सुझाव भी देंगे और हम इसके लिए आग्रह भी करेंगे। मैं कह रहा हूं कि केवल ऑयल सीड उत्पादन के लिए ही नहीं, बायो डीज़ल के उत्पादन के लिए भी केवल सुझाव ही नहीं, सहायता करने के लिए नेशनल बायो डीज़ल मिशन अंतिम प्रक्रिया में है, अंतिम स्टेज में है, उसे हम तुरन्त शुरू करने जा रहे हैं। इस साल पचास करोड़ का बजट प्रोविज़न है, आगे और भी बजट प्रोविज़न बढ़ाया जाएगा। बायो डीज़ल उत्पादन के लिए राज्य सरकार के सहयोग के लिए अन्य जो रिसर्च इंस्टीयूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर के सब लोग लगे हुए हैं, रेलवे है, सभी के प्रयत्न से बायो डीज़ल के उत्पादन में केन्द्र सरकार पूरा प्रयास ही नहीं, पूरा सहयोग भी राज्य सरकारों को देगी ताकि डीज़ल की कमी का हम मुकाबला कर सकें।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has stated,—he has also mentioned it in his reply—that the State Government is taking the initiative under the National Rural Employment Guarantee Programme because the moot question is that the initiative has to come from the Central Governments; the State Government is the executing authority. There are lakhs and lakhs of wasteland in this country. Under the Employment Guarantee Scheme, you are going to spend the money for the purpose of giving employment to the people in the rural areas. There, when the hon. senior Member put his supplementary, he said that Jatropha cultivation can be motivated by the Central Government, and that you need not wait for the State Government to come forward. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Central Government would motivate, under the Employment Guarantee Scheme, the Jatropha cultivation which will, definitely, reduce import of oil from other countries.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी महोदय, माननीय सदस्य की भावना से हम सहमत हैं। हम राज्य सरकार को सुझाव देंगे और सहायता भी देंगे।

श्री रविशंकर प्रसाद: मेरी भावना से सहमत नहीं थे। बात यही है। आप मेरी भावना से असहमत थे। उन्होंने कहा तो आप सहमत हो गए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आपकी भावना से भी हमने कहा कि आपका जो सुझाव या भावना है, उसको मानने में कोई हर्ज़ नहीं है। इसलिए आप निराश नहीं हों और नाराज़ नहीं हों। महोदय, राज्य सरकार को हम इसमें सुझाव देंगे और केवल सुझाव ही नहीं, सहायता भी करेंगे।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Both the questions and answers given so far appear to presume that Jatropha is all a good plant. Is the

Minister aware of the fact that Jatropha is definitely a poisonous plant, and public contact and access to it is supposed to be not desireable?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी महोदय, jatropha अंग्रेजी में कहते हैं, हिन्दी में रतनजोत कहते हैं। वह एडिबल ऑयल नहीं है, नॉन एडिबल ऑयल है। उसको खाया नहीं जा सकता इसलिए स्पष्ट है कि वह जहरीला किस्म का होता है लेकिन उसकी जो रोशनी होती है, उससे कालिख नहीं लगता और उसका प्रयोग गांव में लोग जलाकर करते हैं। लेकिन जंगली चीज़ है, वेस्ट लैंड में उत्पादन बिना खाद-पानी के भी हो सकता है इसलिए इसको प्रमोट करके, उसको कलैक्ट करके, उसकी क्रशिंग करने के लिए expeller की जरूरत होती है और फिर उसका esterification होता है। उसमें जो मोम होता है, उसको हटाकर असली डीज़ल बनाकर उसको किया जा सकता है। इस पर बहुत अनुसंधान भी चल रहा है और उसके लिए हम सहयोग भी करेंगे।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, it is an admitted fact that, as per the Act, it is the State Governments, which have to formulate employment guarantee schemes. Now, so many obstacles are being faced by State Governments in formulating these employment guarantee schemes. What are the proposals to help State Governments in getting rid of these obstacles? Also, so many public sector undertakings working in rural areas are creating hundreds of job opportunities on daily basis. I want to know whether these undertakings will give credence to these employment guarantee schemes, as envisaged in the Rural Employment Guarantee Act.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें अवरोध है, मेरा कहना है कि राज्य सरकारों से हमारा कोई अवरोध नहीं है, बल्कि इम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून लागू करने के लिए हमारा सहयोग है। हम राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क में हैं और महीने-दो महीने में इम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून को लागू किया जाएगा।

श्री राजू परमार: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या गुजरात गवर्नमेंट ने जट्रोपा उत्पादन करने में सहायता देने के लिए आपके यहां कोई प्रपोजल भेजा है? यदि भेजा है, तो उसका ब्यौरा क्या है? साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा, अभी मंत्री महोदय बार-बार कह रहे थे कि हम सहायता करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप रूरल इम्प्लॉयमेंट के तहत ऐसी कोई स्कीम बनाएंगे जिसे सभी राज्यों में इंप्लिमेंट किया जाए? वह स्कीम आप बनाएंगे या नहीं, इसके बारे में आप बताइए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, गुजरात सरकार से अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अपनी तरफ से जिन राज्य सरकारों ने शुरू किया है, वे हैं - उत्तरांचल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नाबार्ड, सी॰एस॰आई॰आर॰ ने यह सब शुरू

किया है। यदि कोई राज्य सरकार प्रस्ताव करे, तो हम उनका प्रस्ताव भी मानेंगे और उनकी सहायता भी करेंगे।

श्री सभापति: अभी तक तो कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, नेशनल बायो-डीजल मिशन जैसे ही शुरू होगा, सब राज्य सरकारों को हम ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार: सर, हम चाहते हैं कि कोई स्कीम आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जाए, डिपार्टमेंट की तरफ से आप स्कीम बनाइए। ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्कीम बनती है, तो उसको योजना आयोग से सहमति लेनी पड़ती है। उसकी मंजूरी के बाद ही उसको किया जा सकता है।

देश में सौर ऊर्जा संयंत्र

***204. श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सौर ऊर्जा से कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) सौर ऊर्जा संयंत्र अभी तक कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) सौर ऊर्जा से निर्मित की जाने वाली बिजली अन्य स्रोतों की तुलना में कितनी महंगी या सस्ती होती है; और

(घ) भारत में उपलब्ध सौर ऊर्ज का अभी तक कितना दोहन किया जा चुका है?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है

विवरण

(क) सरकार की वित्तीय सहायता से देश में कुल 32 ग्रिड इंटरएक्टिव और प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र संस्थापित किए गए है। 2.1 मेवा. की समग्र क्षमता के साथ इन संयंत्रों से एक वर्ष में लगभग 2.5 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) 32 ग्रिड इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)